भोपाल | मंगलवार | 30 जून 2026 | वर्ष 70 | अंक 157 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 सरकार चंदा चोरों को बचा रही : केजरीवाल

4 जुलूस में शामिल लोग सतर्कता बरतें

9 गोयल ने एथेंस में मंत्री से की मुलाकात

11 39 साल की उम्र में जीत सकता है, तो वह जोकोविच हैं : विजय अमृतराज

चंपत से 6 घंटे पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा मामला

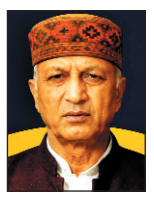

03 महीने पहले ही बैंक ने दी थी चेतावनी | **08** आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में | **13** जुलाई को होगी अगली सुनवाई

चंपत राय | अनिल मिश्रा | टिन्नू यादव | सुभाष चंद्र | लवकुश मिश्रा | अनुकल्प मिश्रा

अयोध्या, 29 जून. अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच एजेंसियों ने वित्तीय लेन-देन की पड़ताल तेज कर दी है. सोमवार को सभी आठ आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने इस चरण में आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी. इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है. तब तक सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

मामले की जांच के क्रम में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी करीब 6 घंटे पूछताछ की गई तथा उनके बयान दर्ज किए गए. पूछताछ के बाद चंपत राय के दिल्ली जाने की जानकारी सामने आई. वहीं, मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस पर छुट्टियों के बाद विचार किया जाएगा. इस बीच अयोध्या के अधिवक्ताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि चढ़ावा मामले के आरोपियों की ओर से कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा. बैठक में कुछ पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने की मांग भी उठाई गई और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई.

दान गबन और चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों के नाम: रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव (ट्रस्ट के महासचिव के पूर्व सहयोगी), सुभाष चंद्र श्रीवास्तव (कैश-काउंटिंग प्रभारी/पूर्व बैंकर) लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामशंकर मिश्रा.

चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- इतनी जल्दबाजी क्यों?

नई दिल्ली, 29 जून. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित हेरफेर से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता क्या है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं की जाएगी और मामले को अदालत की छुट्टियां समाप्त होने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे के कथित गलत इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की है.

तीसरे दिन चंपत राय अयोध्या से दिल्ली पहुंचे

इस्तीफे के तीसरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय अयोध्या से दिल्ली पहुंचे हैं. राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे पूछताछ की और चंपत राय का बयान दर्ज किया है. ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद वे दिल्ली पहुंचे हैं. यह माना जा रहा है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और मामले पर चर्चा कर रहे हैं. अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक आपात बैठक में प्रस्ताव पास कर चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों (अनिल मिश्रा, गोपाल राव) को अयोध्या छोड़ने के लिए तीन दिन का समय दिया है.

पीएम मोदी ने नवशक्ति विनायक मंदिर में की पूजा

नई दिल्ली, 29 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेशेल्स के विक्टोरिया में अरुल मिहु नवशक्ति विनायक मंदिर का दौरा किया और पूजा-अर्चना की. पीएम मोदी का मंदिर के बाहर भारतीय प्रवासी सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

यह द्वीप-समूह का एकमात्र तमिल हिंदू मंदिर है और भारतीय समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मौजूदगी का प्रतीक है. भगवान विनायक (गणेश) को समर्पित यह मंदिर अपनी शानदार द्रविड़ वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। सेशेल्स में एक खास पहचान रखने वाला यह मंदिर भारत और सेशेल्स के बीच लोगों के आपसी और सांस्कृतिक गहरे संबंधों को दर्शाता है।पीएम मोदी ने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने सेशेल्स में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर शनिवार को सेशेल्स पहुंचे थे. सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में रविवार को पीएम मोदी अतिथि के रूप में शामिल हुए.

(शेष पेज 12 पर)

अफगानिस्तान में हवाई हमला, 35 की मौत

- सीमा पार सैन्य कार्रवाई में हुई मौतें
- अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले

इस्लामाबाद/काबुल, 29 जून. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की सीमा से सटे कई क्षेत्रों में सैन्य अभियान और हवाई हमले किए हैं। इस कार्रवाई में कुल 35 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।

पाकिस्तान सरकार के अनुसार यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों पर बढ़ते हमलों के जवाब में चलाया गया, जिसमें पहले जमीनी कार्रवाई और बाद में हवाई हमले शामिल थे। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया था। इसके बाद अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में स्थित संदिग्ध ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। इन हमलों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के अनुसार बाजौर में हुई जमीनी कार्रवाई के दौरान एक कथित कमांडर समेत चार आतंकियों को मार गिराया गया।

संध्या राय बन सकती हैं मोदी कैबिनेट में मंत्री

भिंड, 29 जून. मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी तेजी से चल रही है. भिंड से सांसद संध्या राय का नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में आगे है. इस फेरबदल में प्रदेश से 3-4 नये चेहरों को जगह मिल सकती है. वर्तमान में मध्यप्रदेश से 5 लोकसभा सांसद और एक राज्य सभा सांसद मोदी कैबिनेट में मंत्री है. इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराजसिंह चौहान और डॉ. वीरेन्द्र कुमार कैबिनेट मंत्री है.

एक नजर में

दो दिनी दौरे पर मुर्मु जाएंगी आंध्र प्रदेश

नयी दिल्ली, 29 जून. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जायेंगी. राष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को बताया कि श्रीमती मुर्मु मंगलवार को विजयनगरम में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ़ आंध्र प्रदेश के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बुधवार को वह अनंतपुरम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ आंध्र प्रदेश के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

पीएम मोदी की सचिवों संग बड़ी बैठक आज

नई दिल्ली, 29 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी विभागीय सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे. इस उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे सुधारों, नियमों में ढील, उदारीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और नागरिकों के लिए जीवन को अधिक सुगम बनाने (ईज ऑफ लिविंग) से जुड़े सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना है.

गुस्ताखी माफ

राजस्थान और हरियाणा में समझौता

नई दिल्ली 29 जून. राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में सोमवार को यहां एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों राज्यों में पानी से जुड़ी तीन दशक पुरानी समस्या का समाधान हो जायेगा.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग तीन दशक पुरानी समस्या का आज समाधान हो गया है.

तीन दशक पुरानी समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकता है

शाह ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद के मंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह इस बात का प्रमाण है कि अगर राज्य सहकारी संघवाद की सोच को आगे बढ़ाएं तो तीन दशक पुरानी समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर तक तीन भूमिगत पाइपलाइनों के जरिये लगभग 580 घन मीटर पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा.

नियम उल्लंघन पर पहली बार मिलेगा सुधार नोटिस

नई दिल्ली, 29 जून. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत पहली बार प्रक्रियात्मक या नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के लिए सुधार नोटिस की व्यवस्था लागू की है। जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत लागू इस व्यवस्था में संबंधित संस्थाओं को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया जायेगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

शॉपिंग के लिए केतन से लिए थे 1 करोड़

पुणे मर्डर केस : हत्या से पहले कई चरणों में बनी थी कथित साजिश

पुणे, 29 जून. पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने कई नए तथ्यों का खुलासा करने का दावा किया है। जांच के अनुसार, केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल की नवंबर 2025 में सगाई हुई थी और दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थीं.

पुलिस का कहना है कि इसी दौरान सिया ने शादी की खरीदारी के नाम पर केतन से करीब एक करोड़ रुपये लिए थे. जांच में यह भी आरोप है कि यह राशि कथित रूप से चेतन चौधरी को दी गई। जांच के दौरान 6 जून को केतन और सिया को एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब चालक वैभव जाधव का बयान भी दर्ज किया गया है. चालक के अनुसार, यात्रा के दौरान सिया किसी बात को लेकर अपने भाई से फोन पर बहस कर रही थी.

उसने यह भी बताया कि रास्ते में वाहन कुछ देर के लिए रुका, जहां चार अन्य लोग सवार हुए. बाद में फूड कोर्ट पर रुकने के दौरान सिया कथित रूप से गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में रखकर वापस चली गई. चालक के अनुसार, बाद में उसे सूचना मिली कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है, लेकिन तलाशी के दौरान पासपोर्ट नहीं मिला.

पुलिस का दावा है कि घटना से एक दिन पहले सिया और चेतन ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात कर कथित योजना बनाई थी. जांच के अनुसार, चेतन स्कूटर से लोहगढ़ किले पहुंचा ताकि टोल प्लाजा पर वाहन का रिकॉर्ड न बने. पुलिस ने संबंधित स्कूटर जब्त कर लिया है।

जर्मनी में गोलीबारी : पांच लोगों की मौत, एक संदिग्ध गिरफ्तार

स्टाड (जर्मनी), 29 जून. जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाड में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार, पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। ल्यूनेबर्ग पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में लोगों से घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल पर बचाव कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना स्टाड शहर के मध्य क्षेत्र स्थित एक युवा केंद्र में हुई।

सीबीएसई की नई त्रि-भाषा नीति लागू

- 2026-27 से लागू होगी सीबीएसई की नई भाषा व्यवस्था
- कक्षा 9 से तीन भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली, 29 जून. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप त्रि-भाषा नीति को लागू करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 के छात्रों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और वे पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे. नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9 के सभी छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा. इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी. यदि कोई छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहा है तो वह तीसरी भाषा के रूप में किसी अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी, फ्रेंच अथवा जर्मन जैसी विदेशी भाषा का चयन कर सकेगा. वहीं, जो छात्र एक भारतीय और एक विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा लेना अनिवार्य होगा. जिन विद्यार्थियों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, उन्हें एक बार की विशेष छूट के तहत केवल एक अतिरिक्त भारतीय भाषा जोड़नी होगी. सीबीएसई ने यह भी बताया कि वर्तमान कक्षा 9, 8 और 7 के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. इन विद्यार्थियों को कक्षा 10 में पहुंचने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी. हालांकि, वर्ष 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले और उसके बाद के सभी बैचों को कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होगा.

यूसीसी को लेकर सीएम ने राज्यपाल को दिया ब्यौरा

- लोकभवन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्यपाल से मिले
- यूसीसी को लेकर मिल रहा व्यापक जन समर्थन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 जून. राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक भवन पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल को मप्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, यूसीसी को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन एवं इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्य योजना से भी अवगत कराया.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि यूसीसी बिल को लेकर जिस तरह प्रदेश के लोगों से समर्थन मिला है, उससे प्रदेश में इसे लागू करने को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर स्वीकृति की मुहर लग गई है. सीएम ने राज्यपाल को बताया कि इस बिल को समाज के सभी वर्गों से व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन सबसे बड़ा संतोष का विषय यह है कि इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आगे आई हैं, उन्हें भी इस बिल में अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा होती दिख रही है. बताया जा रहा है कि सीएम ने राज्यपाल को यह भी बताया कि यूसीसी के दायरे से प्रदेश के जनजाति वर्ग को बाहर रखा जाएगा, प्रदेश में यूसीसी लागू होने से जनजाति वर्ग के मान्यताओं, परंपराओं, धार्मिक-रीति-रिवाजों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा.

(शेष पेज 12 पर)

फेरबदल की उम्मीद | सभी मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने को लेकर अनौपचारिक निर्देश

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट शुरू

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 29 जून. केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है. कहा जा रहा है कि सभी मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने को लेकर अनौपचारिक निर्देश दिया गया है.

वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई के शुरुआती हफ्तों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों के दौरे पर जाने वाले हैं. इसलिए माना जा रहा है कि जुलाई के आरंभिक दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा.

> राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं. जहां एक तरफ सरकार की सुस्ती दूर कर मंत्रालयों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने पर फोकस किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर सत्तर पार वरिष्ठतम नेताओं के प्रशासनिक अनुभव के सार्थक उपयोग के लिए बड़े राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं तथा वरिष्ठ नेताओं की सांगठनिक क्षमता का उपयोग कर आगामी चुनावों के लिए भाजपा की जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगाया जा सकता है. हालांकि, मोदी शैली के तहत अंतिम फैसलों में हमेशा चौंकाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए कोई भी भाजपाई वरिष्ठ नेता कुछ भी औपचारिक रूप से बोलने को तैयार नहीं है.

चर्चा है कि वित्त, मानव संसाधन, रेलवे, उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे भारी-भरकम मंत्रालयों की जिम्मेदारी अपेक्षाकृत नए व उर्जावान मंत्रियों को दी जा सकती है. सूत्रों कि माने तो सीतारमण को शिक्षा विभाग, पीयूष गोयल या पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास को वित्त विभाग, अनुराग ठाकुर को रेलवे या वाणिज्य विभाग, इसके अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले नितिन गडकरी के कार्यभार में भी बदलाव कर उन्हें किसी नए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले मंत्रालय की कमान दी जा सकती है. (शेष पेज 12 पर)

पत्रकार टी. विष्णुदत्त जयरामन को मैरीलैंड गवर्नर्स साइटेशन सम्मान

एनापोलिस, 29 जून. भारतीय-अमेरिकी पत्रकार और साउथ एशियन हेराल्ड के संस्थापक-संपादक टी. विष्णुदत्त जयरामन को पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैरीलैंड गवर्नर्स साइटेशन (प्रशस्ति पत्र) से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह सम्मान दक्षिण एशियाई प्रवासियों की आवाज को मजबूती से उठाने के प्रयासों के लिए दिया गया है. यह प्रशस्ति पत्र अमेरिका के मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर ने एनापोलिस में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया.